M.D. : जगदीश ताखर

RAS

SOLUTION

अर्थव्यवस्था

(Economy)

गीतांजलि एकेडमी

RIDHI SIDHI CHAURAHA,NEAR PRAMHANS DHAM,GOPALPURA BYPASS,JAIPUR -9001789123,9529142685
E-Mail : geetanjaliacademy77@gmail.com, Web.: www.geetanjaliacademy.com

Unit - I **(120 Marks)**

(यूनिट – I) **(120 अंक)**

Note : Attempt All questions. Answer the following questions in 15 words each. Each question carries 2 marks. नोट :सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15–15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं।

1. **प्रोजेक्ट सशक्त क्या हैं?**

देश की बैंकिंग प्रणाली में गैर निष्पादित सम्पतियों (NPA) से निपटने के लिए संचालित 5 प्रवृत रणनीति परियोजना
सिफारिश सुनिल मेहता समिति

- SME प्रस्ताव प्रवेश
- बैंक नेतृत्त्व वाले प्रस्ताव प्रवेश
- AMC/AIF
- NCLT/IBC
- एसेट ट्रेडिग प्लेटफार्म

2. **राजस्थान में पशुपालन के लिए चलाई जा रही किन्ही योजनाओं का परिचय दिजिए?**

भेड़ पालकों के लिए – अविका कवच बीमा योजना , गोपालन योजना, मुख्यमंत्री निःशल्क पशु दवा योजना, मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना।

3. **ई रकम ? E- Rakam?**

ई– राष्ट्रीय किसान कृषि मण्डी पोर्टल 1 अगस्त 2017 उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना, इन्टरनेट सुविधा से जोड़ना। इसके तहत ई–पेमेंट के माध्यम से सीधें अपने बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।

4. **राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से संचालित दो योजनाओं के नाम लिखिए–**

1. राजस्थान सड़क क्षेत्र विकास एवं आधुनिकीकरण योजना।
2. राजस्थान ग्रमीण आजीविका मिशन।
3. राजस्थान कृषि क्षेत्र विकास एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक योजना।

5. **प्राथमिक राजकोषीय घाटे को समझाइये? Explain Primary fiscal Deficiat?**

जब राजकोषीय घाटे में से ऋण के ब्याज के लिए अदा किये गए पैसे को घटा दिया जाता हैं
अर्थात् प्राथमिक राजकोषीय घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
P.F.D = (कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत) – कुल आय (राजस्व + पूंजीगत)) – उधार – ब्याज देयता

6. **मोदी केयर से आप क्या समझते है?**

मोदी केयर एक MLM (MULTI LEVEL MARKETING) कम्पनी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी।
उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन उपलब्ध करवाना
केन्द्रीय बजट 2017–18 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना की और अग्रसर होते हुए **आयुष्मान भारत योजना** के नाम से स्थापित मोदीकेयर योजना अमेरिका में ओबामा केयर की तर्ज पर। 10 करोड़ परिवार 5 लाख तक स्वास्थ्य संरक्षण।

7. **वैश्विकरण वास्तविकता अथवा मिथक Globalisation is a Reality or Illusion.**

वास्तविकता	मिथक
• वैश्विक सहयोग हेतु अनेक संगठनों BRICS,G-7, G77, G-20, ईब्सा, SCO आदि की स्थापना	• संरक्षणवाद की ओर मुड़ना Exam - ट्रम प्रशासन – ट्रेड वॉर
• वैश्विक व्यापारिक भागीदारी, तकनीकी आयात बढ़ा	• पिछड़े देश तकनीकी रूप से कमजोर, अतः प्रतिस्पर्धा से बाहर

8. **पैमेन्ट बैंक Payment Bank**

वित्तीय समावेश की दिशा में नचिकेता मोर समिति की सिफारिश पर
1. 1 लाख तक जमा स्वीकार
2. क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, सेविंग एवं करंट दोनों प्रकार की खाता सुविधा
3. डेबिट कार्ड एवं एटीएम सेवा उपलब्ध, पर क्रेडिट कार्ड नहीं

उद्देश्य – लघु बचतों के जमा, निकासी व ब्याज की सुविधा प्रदान करना
उदाहरणः– एयरटैंक बैक, वोडाफोन एम पैसा, आदित्य विडला नूवों लिमिटेड।(कुल 11)

9. **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018?**

World Bank द्वारा जारी विभिन्न मानाकों के आधार पर नये बिजनेस की शुरूआत वेपर हाउस , बिजली उपलब्धता, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, निवेशकों की सुरक्षा, टेक्स पेमेंट, इम्पोर्ट – एक्सपोर्ट नियम आदि के आधार पर व्यापार की सुगमता का मापन 2018 भारत का स्थान 100 वॉ (पहले 130, 30 रैंक की सुधार)

10. **नज इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते है अभी हाल में चर्चा का कारण बताइये।**

GA GENERAL ACADEMY

नज इकोनामिक्स :– यह अर्थशास्त्र की वह अवधारणा है जो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और अप्रत्यक्ष सुझावों को समूह या व्यक्यिों के व्यवहार और निर्णय लेने को प्रभावित करने के तरीके के रूप मे प्रस्तावित करता है।

11. वित्तिय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित प्रमुख समितियाँ

1.नचिकेत मोर समिति
2. दीपक मोहन्ती समिति
3.पार्थ सोम समिति
4. पी.जे. नायक समिति

12. जी.एस.टी. परिषद्

अनु. 279A के तहत गठित
GST क्रियान्वयन एवं सचालन हेतु स्थापित प्रमुख निकाय
2/3 राज्य बहुमत, 1/3 केन्द्र बहुमत
निर्णय 2/3 बहुमत से
कुल 33 सदस्य ।
1. 29 राज्यो के वित्त मंत्री 2. दिल्ली व पाण्डिचेरी के वित्त मंत्री 3. अध्यक्ष – भारत के वित्त मंत्री
4. उपाध्यक्ष – वर्तमान में सुशील मोदी

13. विदेशी मुद्रा भण्डार में क्या–क्या शामिल है ?

1-SDR-S Special Drawingh rights (विशेष आहरण अधिकार)
2. स्वर्ण 3. IMF ट्रेच 4. विदेशी मुद्रा 5. बुलिया

14. 'जुड़वा घाटा' (Twine-Deficit) किसे कहते है ?

चालू खाता घाटा + प्राथमिक घाटा (राजकोषीय घाटा),
प्रभाव – वित्तीय अस्थिरता को खतरा, मुद्रा का अवमूल्यन etc.
Exam- 1999 भारत के समक्ष

15. गिरिंका योजना

रवांडा (अफ्रिकी देश) सरकार की योजना,
पी.एम. मोदी ने 200 परिवारों को गाय भेंट की
सामाजिक सुरक्षा योजना, गरीब परिवारों को डेयरी गाय उपलब्धता हेतु
उद्देश्य – गरीबी उन्मूलन, 305 लाख परिवार लाभान्वित

भाग – ब अंक :50

Note : Attempt All questions. Answer the following questions in 50 words each. Each question carries 5 marks.

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 50–50 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

16. रेन्मिबी (Renminbi) और S.D.R. में सम्बन्ध बताइये।

रेन्मिबी चीन की मुद्रा का अधिकारिक नाम है,
जबकि **SDR** (विशेष आहरण अधिकार), **IMF** (अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष) की कागजी मुद्रा है।
SDR को सम्पूर्ण विश्व मे वस्तु या सेवा के बदले भुगतान के रूप मे स्वीकार किया जाता है।
SDR के सदस्य आपसी विश्वास पर बगैर भौतिक विनिमय के भुगतान की प्रक्रिया अपनाते है।
IMF आरक्षित मुद्रा परिसम्पति, जिसकी बॉस्केट मे 5 मुद्राएं शामिल है, नाम बिग बॉस्केट अमेरिकन – डॉलर, जापानी येन, युरो, पाउण्ड एवं रेन्मिबी । रेन्मिबी सबसे अन्त में शामिल हूई (2015)
रेन्मिबी के बिग–बॉस्केट में शामिल होने से यह भी सार्वभौमिक मुद्रा के रूप में स्वीकार की जायेगी।
सर्वाधिक हिस्सा 31 प्रतिशत डॉलर का, रेन्मिबी हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत।

17. वैश्विकरण का भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वैश्वीकरण तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह भारत द्वारा 1991 एलपीजी सुधारों के अन्तर्गत इसे अपनाया गया

प्रभाव

- सर्वाधिक प्रभाव भारत के सकल घरेलू उत्पाद मे सेवा क्षेत्र पर ही पड़ा प्रत्येक राष्ट्र जहाँ क्रमिक रूप से कृषि → उद्योग व उद्योग → सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था मे बदलते है, भारत सीधा कृषि → सेवा क्षेत्र प्रधान बना।
- बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण
- चतुर्थक क्षेत्र (सेवा) का आर्थिक विकास व **GDP** में 54 प्रतिशत योगदान सम्भव।
- चिकित्सा, सेवा, होटल, परिवहन, दूरसंचार, मनोंरजन के माध्यम से निर्यात सेवाओं मे वृद्वि।
- सेवा क्षेत्र में बाहरी निवेश की सम्भावना।
- भुगतान सन्तुलन मे भारत की अधिशेषी स्थिति।
- विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्वि।
- भारत की असियान ब्रिक्स, अमेरिका तक पहल सम्भव।

18. संविधान के 101 वें संशोधन अधिनियम 2016 की प्रमुख विशेषताऐ बताइये एवं इसके अर्थव्यस्था पर पडनें वाले प्रभावों को भी समझाइये?

Explain the Salient Features of constitution Amendment Act 2016.

वस्तु एवं सेवा कर (101 वां अधि.)

अप्रत्यक्ष करो की दिशा मे महत्वपूर्ण सुधार,

"एक देश एक कर" का विचार।

एकीकृत बाजार की अवधारणा

122 वाँ स. स. के रूप में संसद मे पेश

विशेषताऐं:–

- सविंधान में अनु. 268A, 269A, 279A जोड़े गये।
- इसके तहत **IGST, CGST** व स्टेट **GST** का प्रावधान।
- सम्पूर्ण भारत वर्ष मे लागू।
- **GST** परिषद का गठन,
- **GST** नेटवर्किंग की स्थापना।
- केन्द्रीय बिक्री कर, उत्पाद कर जैसे 17 महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर समाहित अर्थात् मुनामारोधी प्राधिकरण।
- कयोजिशन स्कीम, दर निर्धारण 0,5,12,18,28,32
- सहयोगात्मक संघवाद की दिशा मे महत्वपूर्ण पहल।
- गंतव्य
- लक्ष्य आधारित संकल्पना।

सकारात्मक	नकारात्मक
1 आर्थिक बाजार का एकीकरण अर्थात एकल बाजार 2 कर बाजार का सरलीकरण व सरल कर संरचना 3 सरकार के राजस्व आय में वृद्वि 4 प्रतिस्पर्धी बाजार की स्थापना 5 निर्यात वृद्वि 6 कैस्केडिंग प्रभाव कर के उपर कर की समाप्ति।	1 उत्पादक राज्यों को कर राजस्व की हानि। 2 तकनीकी जटीलता 3 व्यापारियों की जागरूकता की कमी के कारण समझने में मुश्किल। 4 प्रारम्भिक स्वरूप में मुद्रास्फीति 5 वस्तुओं का स्लेब अच्छी तरह विभाजित नहीं।

19. F.D.I. एवं F.P.I. में क्या अन्तर है ?

F.D.I.	F.P.I.
1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश **(Foreigndirect Investment)** 2 पूंजी के साथ– साथ तकनीकी 3 दो ब्राण्ड – मल्टी, सिंगल 4 10 प्रतिशत से अधिक निवेश 5 वस्तुओं, सेवाओं, आधारभूत संरचना में निवेश 6 भौतिक पूंजी का निवेश, विश्वसनीय व स्थायी पूंजी निवेश 7 बम्बई, दिल्ली रूट 8 रोजगार मे वृद्वि व प्रबन्ध कौशलका आगमन	1 विदेश संस्थागत निवेश **(Foreign Portfolio Investment)** 2 तकनीकी नहीं 3 कोई ब्रांड नहीं 4 10 प्रतिशत से कम निवेश 5 शेयर बाजार मे निवेश 6 अस्थिर पूंजी निवेश 7 2 प्रकार **FII-** सस्थागत निवेश **QPS-** व्यक्तिगत निवेश

GA
GEETANJALI ACADEMY

	8 आगमन नहीं

20. समावेशी संवृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या है? क्या भारतीय विकास समावेशी है विश्लेषण किजिए।

What are the Salient feature of enclusive growth.

समावेशी सवृद्वि = विकास का वितरणात्मक पहलू + समस्त क्षेत्र + वित का क्षैतिज वितरण अर्थात् सर्वागीण विकास।

1 अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों – कृषि उद्योग व सेवा
2 समाज के समस्त वर्गों (गरीब–अमीर, वंचित तबका, महिलाओं, वृद्वो, बच्चों, अल्पसंख्यको, पिछड़े लोगों आदि)
3 सभी पहलुओं (आयामों) (सामाजिक – आर्थिक – राजनैतिक सांस्कृतिक)
4 सभी क्षेत्रों (पहाड़ी, मैदानी, पठारी, मरूस्थली आदि) तक सुलभ पहुँच।

भारतीय विकास समावेशी है, सहयोगात्मक सघंवाद प्रकार का है जिसके प्रमाण है।

1 पिछड़े वर्गों को सामाजिक – आर्थिक आधार पर आक्षरण (ST,SC,OBC,SBC,etc)
2 लोककल्याणकारी योजनाएं (भामाशाह, उज्जवला, मनरेगा, सौभाग्य, आयुष्मान भारत)
3 सवैधानिक आदर्श– समानता का अधिकार (अनु. 14,15,16)
4 योजना निर्माण मे प्रत्येक वर्ग की भूमिका व योजनाओं की लोगों तक सरल पहुच (न्याय आपके द्वार)
5 समाजवाद एवं पूँजीवाद का मिश्रित मॉडल
6 12पंचवर्षीय परियोजना, 6–वार्षिक योजनाएं, JAM, नीति आयोग (3,7,15 वर्ष)

परन्तु अमड़ी–पिछड़ी जाति संघर्ष, ऊच–नीच, अमीर–गरीब, असवर्ण–सवर्ण, जातिगत भेदभाव के मध्य बढता अन्तराल आदि इस राह में बाधा है।

21. भारतमाला परियोजना कि उपयोगिता बताइये?

भारत में आधारभूत सरचंना एवं अवसंरचनात्मक विकास से सम्बधित
स्थलीय सीमा के सहारे स्थित क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की परियोजना अर्थात् राजमार्ग गलियारे निर्माण की योजना।

1 बन्दरगाहो और सड़को, नेशनल कॉरिडोर्स को ज्यादा बेहतर बनाना।
2 पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटक स्थल को जोडने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाकर विकसित करना, चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और स्वर्णिम चतुर्भुज भी शामिल
3 सड़के आर्थिक विकास का ईंजन अतः इनके विकास से परिवहन व्यवस्था सुदृढ जिससे स्मार्ट सिटी, ग्लोबल सिटी का विकास सम्भव
4 सम्पूर्ण खाद्य श्रंखला को कोल्ड चेन के माध्यम संगति
5 औद्योगिक विकास को गति
6 अत्याधुनिक सुविधाओ का विकास सम्भव
7 सेना हेतु आपातकालिन स्थिति मे सहायक
8 निर्जन व बंजर क्षेत्रों मे बसावट में सहायक
9 सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण (पाकिस्तान,चीन, श्रीलंका आदि पड़ोसी देश)

22. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद(ECOSOC) के प्रमुख कार्य बताइये?

What are the main function of the United Nations Economic and social councile.

ECOSOC- The United Nations Economic and social council

स्थापना 1945, 54 सदस्य

सयुक्त राष्ट्र आर्थिक–सामाजिक परिषद UNO के प्रमुख अंगों मे से एक है।

प्रमुख कार्य :–

- सदस्य राष्ट्रो के आर्थिक–सामाजिक मसलों पर सहायता व परामर्श उपलब्ध करवाना
- सदस्यो राष्ट्रो को तकनीकी सहायता व परामर्श के साथ आर्थिक–सामाजिक मुद्वो पर विवाद की स्थिति में हस्तक्षेप भी करती है।
- यह संस्था सामान्य सभा को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहायोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता एवं सामाजिक समस्याओं से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है।
- लैगिक भेदभाव, अशिक्षा, असमानता, गरीबी, कुपोषण आदि की पहचान कर उन पर चर्चा करना।

23. भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारों (Industrial Corridors) को रेखांकित किजिए एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में इनके महत्व की चर्चा कीजिए।

भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारे

- दिल्ली–मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर
- मुम्बई–बैंगलोर इकोनोमिक कॉरिडोर
- चैन्नई–बैंगलोर
- अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता
- VANPIC- VADREVU AND NIZAM PASTNAM PORT INDUSTRAL CORRIDOR

GA GETAWAY ACADEMY

- उडाना–पलसाना कॉरिडोर etc.

महत्व

- सन्तुलित क्षेत्रीय विकास
- निर्यात प्रोत्साहन
- सकल घरेलू उत्पाद में वृद्वि
- लोगो के सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक जीवन स्तर में वृद्वि
- आधारभूत संरचनात्मक विकास
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने में सहायक
- रोजगार मे वृद्वि, कर राजस्व मे वृद्वि

24. सहायिकिया (Subsidies) से आप क्या समझते है? भारत में किसानों की आर्थिक स्थति को यह किस प्रकार प्रभावित करती है?

सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को आर्थिक विकास की सहायतार्थ प्रदत्त राशि या अप्रत्यक्ष सहायता सहायिकी कहलाती है। अर्थात् बाजार मूल्य से कम मूल्य पर वस्तुए एवं सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रदत वितीय सहायता सब्सिडी कहलाती है।

उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों को लाभ पहुचाना

देयता– 1 नकद भुगतान या प्रत्यक्ष 2 कर कटौती के रूप में अप्रत्यक्ष

विभिन्न सब्सिडिया– उत्पादन, रोजगार, परिवहन कर, धार्मिक, खाद्य, उद्योग, उर्वरक, खाने के समान, हजयात्रा, ईधन, वस्त्र आदि

सकारात्मक प्रभाव

- कृषको की उत्पादकता मे वृद्वि
- बेरोजगारी में कमी
- प्रदूषण को कम करने हेतु परिवहन सब्सिडी
- औद्योगिक विकास
- खाद्य उद्योगो को बढ़ावा
- कृषि निवेश में वृद्वि
- मानसून अनिश्चिता व ऋण भार से बचत

नकारात्मक प्रभाव

- बाजार को अव्यवस्थित करती है
- कुछ ही किसानों तक
- कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित

25. खाद्य प्रक्रमण इकाईयां गरीब किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक हो सकती है स्पष्ट कीजिए?

How the food processing unit will be helpfull to uplift the socio-economice States of poor farmers.

आर्थिक

- कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने मे सहायक
- बाजार मांग के अनुसार किसानों को फसल उगाने मे सहायक
- खाद्यान फसलों के साथ नकदी व्यापारिक फसलों को भी उपजाने मे सहायक
- खेतों से मण्डियों तक लगने वाले परिवहन व्यय मे कमी
- ई–मण्डियों की स्थापना, कृषि सब्सिडी का विस्तार
- किसानों को बिचौलिया के शोषण से बचाती है
- यह कृषि उत्पाद प्राप्त कर उनकी गुणवता सुधार व मूल्य सवंर्धन कर बाजार तक पहुचाती है।
- किसानों की आय में वृद्वि

सामाजिक

- आय मे वृद्वि के परिणामस्वरूप कृषक प्रतिष्ठा मे वृद्वि
- शिक्षा की ओर अग्रसर
- लघु,मध्यम,कुटीर कृषि उद्योगो का विकास
- नई तकनीको के ज्ञान से जागरूकता में बढोतरी
- महिलाओ की भूमिका व भागीदारी में बढोतरी

(कुछ उपजो की प्राथमिक स्तर पर खेत मे ही प्रसंस्करण के कारण)

- उत्पादन से उपभोक्ता तक सम्पूर्ण खाद्या श्रंखला को सरल जिससे खाद्यान्नो की अपशिष्टता रोकने मे मदद
- अनुबन्ध कृषि को प्रोत्साहन

GA GEETANJALI ACADEMY

भाग – स अंक :40

Note : Attempt All questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 marks. नोट :कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100–100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

26. "भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राजकोषीय कानूनों में जी.एस.टी. कानून मिल का पत्थर साबित होगा" आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

जी.एस.टी. 'एक राष्ट्र एक कर' की अवधारणा पर आधारित सबसे बडा कर सुधार है

101 वां सविधान संशोधन, 31 जुलाई 2017 से लागू। इसे अप्रत्यक्ष कर सुधारो की दिशा में मील का पत्थर बताया जा रहा है।

इससे जी.एस.टी परिषद, जी.एस.टी एवं केन्द्र राज्य व एकीकृत जी.एस.टी, मुनाफारोधी प्राधिकरण व ई–वे बिल इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था व राजकोषीय कानूनो पर जी.एस.टी का प्रभाव

सकारात्मक

- एकीकृत आर्थित बाजार का निर्माण
- GDP में वृद्वि
- कराधार विस्तृत जिससे आर्थिक समानता की ओर उन्मुखता
- बहुत सारे अप्रत्यक्ष करो (VAT, सेवा कर, बिक्री कर)के स्थान पर केवल एक कर
- कई उघोगों व व्यापारों का औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होना
- 'एक देश एक कर' के कारण विदेशी निवेश (FDI,FII)को प्रोत्साहन व आकर्षण
- वैश्विक स्तर में रैटिंग में सुधार(फिच,मूडीज)
- ईज ऑफ डूंईग बिजनेस मे सुधार 100 वा स्थान
- मुद्रा स्फीति में कमी (कैस्कैडिग प्रभाव को खत्म करने के कारण)
- कालाबाजारी व भ्रष्टाचार में कमी
- करों की जटीलता कम, जिससे कर अपव्यय में कमी
- राजस्व घाटे में कमी
- सरकार की कर योग्य आय में वृद्वि
- अप्रत्यक्ष करो का राजस्व आय में योगदान बढेगा
- राजकोषीय घाटे के आदर्श लक्ष्य $3\% \pm 0.5$ तक ले जाने पर केन्द्रित होगे
- राजकोषीय नीति को प्रभावी बनाने मे सहायक

नकारात्मक

- तकनीकि जटीलताएं (रिटर्न दाखिल करने में)
- 5 कर स्लैब (0,5,12,15,28) प्रतिशत जो कि अधिक
- अधिकांश वस्तुए 18 व 28 प्रतिशत की स्लैब में
- शैक्षणिक पिछड़े पन व जनजागरूकता के कारण व्यापारियों को समझने में मुश्किल
- गन्तव्य आधारित कर होने के कारण उत्पादक राज्यों को हानि
- दैनिक उपभोग वस्तुओ के टैक्स स्लैब में आने से उपभोक्ताओ पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

27. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) क्या है? इसमें व्याप्त "लूट,लिकेज लॉस" का उन्मूलन के उपाय बताइये

PDS भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 47 की अनुपालना में देश के सभी लोगों के पोषण स्तर में सुधार हेतु प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुओं की बहुत ही कम कीमत पर आपूर्ति।

भारत में खाद्यान्न लीकेज लगभग 4.6 प्रतिशत हैं जबकि, छतीसगढ में 0.1 प्रतिशत है।

लूट से तात्पर्य मध्यस्थों का होना, सार्वजनिक प्रणाली में भ्रष्टाचार।

लीकेज का तात्पर्य रिसाव अर्थात् लाभार्थी तक न पहुँच पाना।

लॉस से तात्पर्य खाद्य गुणवत्ता मानको में गिरावट व कम खाद्यान्न पहुँचना है।

GA GENIUS ACADEMY

इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीद, भण्डारण, परिवहन व आंवटन तथा राज्य सरकारो द्वारा खाद्यान्न वितरण का कार्य किया जाता है।

3L(लूट,लिकेज लॉस):– सही लाभार्थी का चयन होना, खाद्यान्न बाजार में विक्रय व पूर्ण रूप से आवंटन न होना, खाद्यान्न बाजारो में व गोदामो मे अनाज सड़ना आदि समस्याएं

उन्मूलन के उपायः–

- प्रत्यक्ष लाभ हस्तानान्तरण (DBT) लागू करना
- राशन की दुकानों का कम्प्यूटरीकृत किया जाना,
- ऑनलाइन आवंटन करना
- पॉस सिस्टम लागू।
- पंचायती राज संस्थाओ द्वारा PDS प्रणाली का अंकेक्षण
- खाद्यान्न परिवहन साधनों पर GPS सिस्टम लगाया जाना
- शांता कुमार समिति के अनुसार PDS वितरणकर्ता के डिसकाउट में वृद्वि की जायें
- प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों का क्षेत्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवाया जाए
- PDS का विस्तार किया जाये
- FSSAI द्वारा प्रमाणित गुणवता युक्त खाद्यान्नों का वितरण किया जाए
- खाद्यान्नो मे स्थानीय पसन्द का ध्यान रखा जाये
- खाद्यान्नो के सन्दर्भ मे भी नकद सब्सिडी लागू की जाए (शांता कुमार समिति)
- सभी लोगों के आधार कार्ड से जोड़ा जाऐ
- JAM ट्रिनिटी व BAM का प्रयोग
- छतीसगढ़ मॉडल के आधार पर इसका वितरण NGO व SHG (स्वयं सहायता समुह) द्वारा
- डोर स्टेप डिलिवरी सुनिश्चित हो।
- राशनडीलरों के यहां तौल व माप हेतु इलेक्ट्रोनिक काटो की अनिवार्यता हो

NOTE :– राजस्थान में फ्यूचर ग्रुप से अनुबन्ध कर अन्नपूर्णा भण्डार योजना लाई जा रही है। इसके अलावा सीडिंग व आधार बेस्ट बायोमैट्रिक औथेरिकेशन (ABBA) को भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

28. भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों (Poverty alleviation Programmes) की सफलता में प्रमुख बाधक तत्वों को रेखांकित किजिए एवं भारत सरकार के गरीबी उनमूलन कार्यक्रमों के निष्पादन (Performance) पर संक्षिप्त चर्चा किजिए?

''वंचितता से मुक्ति गरीबी निवारण की अनिवार्य शर्त है,'' गुन्नार मिडेल

प्रमुख बाधक तत्वः–

- लोगों मे व्याप्त शैक्षणिक पिछडापन
- जागरूकता की कमी
- सरकारी योजनाओ के प्रचार–प्रसार में कमी
- प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लक्षित समूह को लाभ नहीं
- लालफीताशाही
- सूचना तकनीकी अवधारणा का कम विकसित होना
- दुर्गम क्षेत्रों तक पहुच न होना
- सहायता राशि अत्यन्त कम होने के कारण गरीबी उन्मूलन मे कम सहायक
- योजनाओ मे एकरूपता का न होना अनेक योजनाओ के स्थान पर एक ही योजना का निर्माण किया जाए
- योजनाओ का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन न होना व लेखांकन तथा सामाजिक अकेंक्षण का अभाव
- गरीबी निर्धारक सर्वमान्य पैमाना नही, सुरेश तेदुंलकर के अनुसार 14.7 प्रतिशत गरीब व रंगराजन के अनुसार 21.7 प्रतिशत
- योजनाओ का केन्द्र बिन्दु केवल ''गरीबी कम करना'' आधारभूत संरचनात्मक विकास व रोजगार निर्माण नहीं
- राजनीतिक स्टट के रूप में प्रयोग – सरकार परिवर्तित होने पर योजना का परिवर्तत होना
- जनसंख्या भार
- कृषि पर आश्रितता

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमः– महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, बीस सूत्री कार्यक्रम, सांसद विधायक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पी एम आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल।

वर्तमान में नीति आयोग का निर्माण – दिशा पोर्टल का विकास, योजनाओं के निष्पादन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका व सामाजिक अंकेक्षण आदि प्रयास किये जा रहे है।

29. लक्षित मुद्रास्फीति (Targeted Inflation) क्या होती है? मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

GA GENIUS ACADEMY

मुद्रा स्फीति – सामान्य कियत स्तर में वृद्वि से है अर्थात् वह स्थिति जिसके वस्तुओं के मूल्य बढ़ते है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है।

मुद्रास्फीति
- मांग प्रेरित
- लागत प्रेरित

NOTE :– मुद्रासंकुचन/अवस्फीति इसके ठीक विपरीत है।

लक्षित मुद्रास्फीति :– किसी राष्ट्र की वांछित वृद्वि दर प्राप्त करने हेतु सरकार की राजकोषीय व मोद्रिक नीति के तहत लक्षित दर ही लक्षित मुद्रास्फीति कहलाती है।

भारत मे RBI द्वारा मुद्रास्फीति के सम्बन्ध में निर्णय हेतु कार्यकारी स्वायतता प्राप्त थी परन्तु हाल ही में मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया जिसके 3 सदस्य RBI से व 3 सदस्य सरकार द्वारा नामित है।

मौद्रिक नीति समिति द्वारा भारत मे खुदरा मुद्रा स्फीति में 4 प्रतिशत (±2) की लक्षित मुद्रास्फीति तय की गई है।

सकारात्मक प्रभाव

- आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलती है
- ऋणदाताओ को हानि तथा ऋणी को लाभ होता है
- इससे उत्पादक वर्ग को लाभ होता है क्योंकि कीमतों में वृद्वि होती है।
- मुद्रा का मूल्य कम (रू↓) जिससे उत्पादन मे वृद्वि को प्रोत्साहन
- आधारभूत संरचनागत विकास
- आयात प्रतिस्थापन को बल
- कर राजस्व में कमी
- घरेलू उत्पादन में वृद्वि

नकारात्मक प्रभाव

- मुद्रा का मूल्य कम होना
- आयात प्रतिस्थापन
- अधिक होने पर मुद्रा का अवमूल्यन
- सरकार के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में कठिनाई
- उद्योगों के बन्द होने से बेरोजगारी की समस्या
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक मे कमी
- जीवन स्तर प्रभावित

इस प्रकार मुद्रास्फीति का एक निश्चित स्तर तक किसी अर्थव्यवस्था को लाभ है और उससे ऊपर नीचे ही हानि की सम्भावना रहती है।

मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित कर 4% ± 2% उसके प्रभावों की समीक्षा करना है और RBI मौद्रिक समिति का प्राथमिक कार्य लक्षित मुद्रास्फीति हो गया है व राजकोषीय नीति भी इसी पर केन्द्रित है।

Part - A **Marks:20**
भाग – अ **अंक :20**

Note : Attempt All questions. Answer the following questions in 15 words each. Each question carries 2 marks. नोट :सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15–15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं।

1. वित्तिय विवरण विश्लेषण की प्रमुख तकनीके बताइये।

कुल 8 तकनीके

- तुलनात्मक वितीय विवरण विश्लेषण–परिसम्पतियों एवं दायित्वों की तुलना
- प्रवृति विश्लेषण– जोखिम लेने की क्षमता, ग्राहकउन्मुखी
- समानााकार वित्तीय विवरण– समस्त कारको को प्रतिशत मे दशार्या जाता है
- अनुपात विश्लेषण – विभिन्न गतिविधियों में अनुपात निकाला जाता है जैसे लागत–लाभ अनुपात (सबसे लोकप्रिय)
- कोषप्रवाह विश्लेषण – बहेतर नियोजन
- रोकड़ प्रवाह विश्लेषण

GA
GETANJALI ACADEMY

- समविच्छेद विश्लेषण (न लाभ, न हानि)

2. **बायोपाइरेसी क्या हैं?**
यह जैविक संसाधनों के आधार पर नए उत्पादों की खोज और व्यावसायीकरण की प्रक्रिया है।
अर्थात् किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता के कारण प्रसिद्व उत्पाद को अन्य किसी राष्ट्र या कम्पनी द्वारा पेटेन्ट कराकर स्वयं का सिद्व करना Exam:– अमेरिका ने नीम (भारत) को बायोपाइरेसी मे स्वरूप में लेने को प्रयास

3. **स्पोर्टस इंडिया।**
भारत मे खेलो को बढावा देने, आधारभूत सरंचना (खेल सामान व खेल मैदान) उपलब्ध कराने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करने व खेलों में रूचि जागृत करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा खेलों इण्डिया योजना का शुभारम्भ किया गया।
इसमे अखिल भारतीय स्तरीय स्पोटर्स छात्रवृति योजना भी शामिल की गयी, प्रत्येक एथलीट को 1 वर्ष मे 5 लाख की छात्रवृति, 8 साल तक दी जायेगी
उद्देश्य :– प्रतिभाशाली एथलीट खिलाड़ियों को शिक्षा और आर्थिक समस्या के बिना प्रतिभा के दम पर आगे बढने के लिए प्रोत्साहित करना है।

4. **जी– 7 शिखर सम्मेलन?**
44 वां जी–7 शिखर सम्मेलन 8,9 जून 2018 व क्यूबेक कनाडा मे आयोजित
यह एक राजनीतिक और आर्थिक अनुसंधान और सलाहकार फर्म है इससे समृद्व विकसित औद्योगिक देश शामिल है (कनाडा,फ्रांस,जर्मनी,USA,UK,इटली व जापान)

5. **निष्पादन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। What do you understand by Performance appraisal?**
निष्पादन मूल्याकन, कर्मचारी मूल्याकंन के रूप में ज्ञात एक ऐसी विधि है, जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य निष्पादन का मूल्याकंन किया जाता है (साधारणतया गुण, मात्रा, लागत एवं समय के सम्बन्ध मे) यह जीवन – वृति विकास का ही एक हिस्सा है
उद्देश्य – कर्मचारियों के निष्पादन पर प्रतिपुष्टि देना, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना
प्रमुख विधियाः–
- उद्देश्य–आधारित प्रबन्धक
- 360 डिग्री मूल्याकंन
- व्यवहारिक अवलोकन मानदण्ड
- व्यवहारिकी स्थिर श्रेणी मानदण्ड

6. **कैच–बॉल मेथड Catch ball Method.**
Catch ball Process
- Group Goals & Priorities
- Division objectives
- Department objectives
- Section objectives
- frotline objectives

संगठन मे सहयोग, हर स्तर पर अलग–अलग कार्यनिर्धारण, प्रभावी निष्पादन, प्लानिंग, डायरेक्शन, बजटिंग आदि हेतु उपयोगी मैथड जापान से गृहण सहयोग की भावना पर आधारित।

7. **जीरों बैस बजट (Zero Base Bugzet) क्या हैं? इसे भारत में पहली बार कब लागू किया गया।**
अन्य नाम सूर्य अस्त बजट (Sunset Budget)
अमेरिका से प्रारम्भ 1973 जनक पीटर ए पायर,
भारत मे शुरूवात 1987–88 के बजट में
वह बजट प्रणाली जो विगत वर्षों के लिए किये गये व्ययो पर विचार नही करती और न ही विगत वर्षो के व्ययों को भावी वर्ष के लिए प्रयुक्त करती है बल्कि यह प्रणाली इस बात पर बल देती है कि व्यय किया जाए या नही
उद्देश्य – देश के बजट में निरन्तर पाया जाने वाला घाटा (व्यय↑ आय↓)

8. **अंकेक्षण की सीमा बताइयें। Write the limitations of Auditing (any 4)**
- व्यवहारों के औचित्य को प्रमाणित नही करता है।
- अकेक्षण का कार्य केवल राय /सुझाव प्रकट करना।
- समस्त गबन पकड़े जाना सम्भव नही।
- कर्मचारियो की ईमानदारी का पूर्ण प्रमाणन नही।
- अकेक्षण शत–प्रतिशत शुद्वता की गारन्टी नही देता है।

GEETANJALI ACADEMY

9. भारत वाटवाणी हाल ही में क्यों चर्चा में रहें?

भारत वाटवानी व सौनम वागंचुक को हाल ही मे रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

कारण – मानसिक रोगियो का इलाज करने, भीख मांगने वालों का इलाज करने (1988, श्रद्वा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन की स्थापना)

10. जी.आई. टैग क्या हैं? What is GI TAG?

यह किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है (**Geographical Indicator**) यह टैग उसी उत्पाद को दिया जाता है (1) जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है। (2) जिससे निहित विशेषताओ का उस स्थान विशेंष से गहरा सम्बन्ध होता हैं।

प्रमुख उत्पाद – काचीपुरम सिल्क साडी, अलफासो मैगो, नागपुर ऑरेन्ज, कोल्हापूरी चप्पल,बीकानेरी भुजिया, कालबेलिया नृत्य, मौलेला मृणमुर्ति कला, फूलकारी, पेवाकला, मकराना मार्बल, बगरू प्रिन्ट, कोटा डोरीया साडी, कठपूतली, ब्ल्यूपाटरी–जयपुर।

भाग – ब **अंक :20**

Note : Attempt All questions. Answer the following questions in 50 words each. Each question carries 5 marks. नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 50–50 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

11. निष्पादन बजट एवं लाईन आइटम बजट में पांच अन्तर बताइए। Differentiate between line item budget and performance budget.

निष्पादन बजट हुवर कमीशन ने प्रयुक्त की (1949), जबकि आइटम बजट परम्परागत बजट है 18वीं–19वीं सदी में विकसित हुआ

निष्पादन बजट	लाईन आइटम बजट
(1) यह बजट व्यय को सीधे उपलब्धियों से जोड देता है।	(1) इसमे वस्तुओं या मद का महत्व अधिक होता है।
(2) इनका उद्देश्य व्यय के स्थान पर व्यय के उद्देश्य पर जोर दिया जाता है।	(2) इसका मुख्य उद्देश्य अपव्यय, अधिक खर्च और बर्बादी को रोकना हैं।
(3) यह नवीन लोक प्रशासन की देन है और वितीय प्रशासन मे सुधार का आवश्यक अंग है।	(3) इसमें सार्वजनिक व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य को प्रमुखता दी जाती है।
(4) इसमे बजट का रूप लोकतांत्रिक हो जाता है।	(4) इसमें व्यय की प्रत्येक मद को पक्तिवार लिखा जाता है।
(5) गतिविधि बजट या कार्यात्मक बजट आदि	(5) इसमे खर्च की जाने वाली राशि पर जोर अधिक रहता है।
(6) निष्पादन पर	(6) अभिवर्धन बजट
(7) कार्यपरिणामोन्मुखी	(7) मदक्रम पर
(8) प्रदर्शन पर बल	(8) खर्च उन्मुखी
(9) नवीन बजट	(9) लक्ष्यो पर केन्द्रित
	(10) पारम्परिक बजट

12. "बजट 2018 में ग्रामीण भारत पर विशेष फोकस किया गया है " क्या आप इस कथन से सहमत है तर्क सहित स्पष्ट किजिए।

हॉ केन्द्रीय बजट 2018 में ग्रामीण भारत पर विशेष फोकस किया गया है। इसमे निम्न बात है

- मनरेगा का विस्तार, 48 हजार करोड़ का आवंटन
- ऑपरेशन ग्रीन के तहत प्याज, आलू, टमाटर हेतु योजना
- किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य
- KCC को विकसित करना, मत्स्य, पशुपालन व बागवानी मे भी
- राष्ट्रीय बांस मिशन
- Gram (ग्रामीण हाट बाजार) व NAM को सयुक्त कर कृषि अधिसंरचना कोष की स्थापना
- 2022 तक सभी को आवास व बिजली उपलब्ध करवाना
- राज्यों में ग्रामीण विकास व कौशल आजीविका मिशन का निर्माण
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन
- न्यायिक व्यवस्था हेतु टेली लॉ प्रणाली
- स्मार्ट गांव निर्माण योजना, आधारभूत संरचनात्मक विकास

GA PATANJALI ACADEMY

- PM ग्रामीण कृषि विकसित सूक्ष्म सिचांई योजना
- स्वयं सहायता समूहों एवं NGO का विस्तार करना Exam- सहेली मार्केट – धोलपुर

13. सामाजिक लेखा – परीक्षण के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर चुनौतियों की विवेचना करें।

Discuss the challenges at **Gram Sabha** level in context of Social Auditing.

सामाजिक लेखा परीक्षा में ग्राम सभा स्तर पर निम्न चुनौतियां है

- स्थानीय लेखा जांच में पूर्णता नहीं
- लेखांकन की पूर्ण जानकारी के अभाव मे अस्पष्टता
- केवल सुझाव ही, निदान प्रस्तुत नही
- प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता
- इच्छाशक्ति का अभाव
- ग्रामीण जागरूकता का अभाव
- दण्डात्मक शक्ति का प्रावधान नही
- योजनाओं के क्रियान्वयन मे ग्राम सभाओं की भूमिका नगण्य होना।
- आन्तरिक अंकेक्षण में कमियां
- राजनीतिक दवाब, जातिय वर्गवाद आदि

14. जेण्डर बजट से आप क्या समझते है? भारत सरकार द्वारा इस हेतु किये गये प्रयासों का उल्लेख कीजिए।

लिंगः– सवेदनशील बजट वह बजट होता है, जिससे महिलाओ व बाल कल्याण को विशेषतया ध्यान में रखा जाता है।

उद्देश्य – लैगिक पदानुक्रमो और महिला–पुरूषों के वेतन के बीच विसंगतियों सहित बजटीय लिंग असमानता के मुद्दो से निपटना महिला सशक्तिकरण में उतरदायी,

2005 मे शुरू प्रयास (1)निर्भया फण्ड, 1000 करोड़ की राशि स्वीकृत (2) बजट निर्माण मे नारीवादियों, महिला संगठनो, महिला आयोग, बाल आयोग, गैर सरकारी संगठनों से परामर्श किया जाना (3) ससंद मे महिलाओ की भागीदारी हेतु विधेयक (4) स्वयं सहायता समूहो को प्रोत्साहन (5) महिला व बाल कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण (6) निर्णय एवं निर्णयण की प्रक्रिया मे महिलाओ की उचित भूमिका व भागीदारी सुनिश्चित करना (महिला सशक्तिकरण)। (7) सुरक्षित शहर योजना के तहत आवंटन, निर्भया फण्ड, महिला शक्ति केन्द्र, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, भामाशाह कार्ड etc.

15. राजस्थान में महिला कल्याण (Women Welfare) के प्रमुख कार्यक्रम कौन–2 से है? किन्ही 2 आर्थिक विकास की योजनाओं को सविस्तार से समझाइये।

(1) भामाशाह योजना (2) सुकन्या समृद्वि योजना (3) मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना (4) ई–सखी योजना (5) नन्ही कली, कन्या कलश, भाग्यश्री, चरणपादुका योजना (6) सहेली मार्केट (7) मुख्यमंत्री राजश्री योजना (8) CM स्वावलम्बन योजना (9) अमृता हाट (10) सी.एम. सात सूत्री योजना (11) जननी सुरक्षा योजना (12) अभय कमाण्ड सेन्टर (13) चिराली योजना

(1) सहेली बाजार– महिला SHG द्वारा महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की ब्रिकी हेतु उपलब्ध बाजार, धौलपुर से शुरूवात (2) भामाशाह योजना :– महिला सशक्तिकरण वां वितीयसमावेशन की दशा मे परिवार के महिला मुखिया के नाम भामाशाह कार्ड, जिससे सरकार की विभिन्न योजनाओं का नगद व गैर नगद हस्तानान्तरण किया जाता है, (DBT Programme) (3) मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजनाः– महिलाओं को स्वरोजगार हेतु CM स्वावलम्बन योजना का संचालन किया जा रहा है।

16. बायोफ्यूल (BIOFUEL POLICY) uhfr ykxw dju okyk jkt LFkku igyk jkT; gA bl uhfr dh e[; fo'k"krk,¡ crkb;sA

राजस्थान सरकार तक वर्ष 2018 में बायोफ्यूल नीति लागू की गई है

विशेषताएं

- इसके तहत रतनजोत, जेट्रोफा, जोजोबा, होहोबा, करांकस के तहत बायोफ्यूल का उत्पादन किया जायेगा।
- इसके क्रियान्वयन हेतु बायोफ्यूल प्राधिकरण की भी स्थापना की गयी हैं।
- इथेनॉल आधारित पेट्रोलियम के उपयोग को मंजूरी
- ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच को मंजूरी
- नये–नये बायोफ्यूल आधारित क्षेत्रो की पहचान
- जैव ईन्धन मे शोध व अनुसन्धान को बढ़ाकर व सरकार द्वारा इस पर सब्सिडी प्रदान

GETANJALI ACADEMY

- बायोफ्यूल के उत्पादन, वितरण व उसकी तकनीकी सम्बन्धी अवसंरचनाओ को मजबूत करना।

भाग –स **अंक :10**

नोट : निम्न प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दें।

17. अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के अनुसार भारत में साइबर अपराध बढ़ा हैं। इस संबंध में विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में साइबर अपराध से निपटने हेतु अपना सुझाव दें।

साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिस में कम्प्यूटर और नेटवर्क शामिल है इसके कई प्रकार है– स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नजर रखना। कम्प्यूटर इलैक्ट्रोनिक माध्यम से डाटा की अनधिकृत चोरी, सग्रहण सारबर अपराध।

अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मत एक दशक मे साइबर अपराध में 350 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। इस सम्बन्ध में गठित विशेषज्ञ समिति के अनुसार साइबर अपराधों के निवारण हेतु केन्द्रीय स्तर पर नोडल एजेन्सी निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ मे समन्वय सहयोग, सरकारी वेबसाइटों में 64 Prit के स्थान पर 256 Prit, एनकिप्शन अपनाया, साईबर अपराधो के सन्दर्भ मे जागरूकता का प्रसार

सुझाव

(1) सूचना तकनीक कानून, 2000 के अन्तर्गत साइबरस्पेस में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रावधान।

(2) भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) में साइबर अपराधों से सम्बन्धित प्रावधानों को ओर विस्तार प्रदान करना, धारा 503,499,463,420,383 आदि

(3) 66–एफः साइबर आतंकवाद के लिए दण्ड का प्रावधान, 2000 से लागू।

(4) साइबर सेल की स्थापना की जायेगी।

(5) साइबर अपराध प्राधिकरण का गठन

(6) साइबर थानों को विकसित करना, पुलिस थानों में हैकरो व साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए ताकि वो हैकिंग को काउंटर कर सके।

(7) अभय कमाण्ड सेन्टरो पर विशेष प्रशिक्षण मुक्त साइबर पुलिस की नियुक्ति की जाए।

(8) पुलिस प्रतिस्पर्द्वात्मकता बढाने हेतु प्रशिक्षण में सुधार लाना

(9) एथिकल हैकिंग को बढावा मिले।

(10) सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सअप) की सामग्री को निगरानी श्रेणी मे लाया जाए।

(11) समस्त विभागों व संस्थाओ में साइबर सुरक्षा उच्चस्तरीय मानकों के अनुसार जैसे – एंटीवायरस

18. साइबर आंतकवाद क्या है (Cyber Terrorism) साइबर आंतकवाद उपकरणों का विवरण दिजिए एवं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उत्पन इस गंभीर चुनौती का विशलेषण कीजिए।

साइबर– आतकंवाद एक वाक्यांश है जिसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियो मे इन्टनेट आधारित हमलो का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमे शामिल है कम्प्यूटर वायरस जैसे साधनो के माध्यम से कम्प्युटर नेटवर्क में जानबूझ बडे पैमाने पर किया गया व्यवधान, विशेष रूप से इन्टरनेट से जुडें, किसी कम्प्यूटर में व्यवधान।

आंतकवादी समूहो और व्यक्तियों द्वारा अपने एजेडे को आगे बढाने के लिए सूचना प्रौद्योगिक का उपयोग, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल किया जा सकता है ताकि नेटवर्को, कम्प्यूटर सिस्टमों और दूरसंचार ढांचा, या जानकारी का आदान–प्रदान या इलेक्ट्रोनिक के माध्यम से धमकियां देने को संगठित और निष्पादित किया जा सके।

साइबर अपराध उपकरण (1) हेट स्पीच (2) आनलाईन कम्यूनिटी (3) नागरिको को बरगलाना (4) साम्प्रदायिक दंगे भडकाना (5) साइबर स्टॉकिग (6) फिशिंग (7) विशिंग (8) स्पैमिग (9) डाटा थ्रोटलिंग (10) हैकिंग (11)कमजोर नेटवर्क मे वायरस डालना (12) वेब साइट वीरूपण (13) सेवा से इन्कार हमला (14) इलैक्ट्रोनिक साधन के माध्यम से आतंकी धमकी आदि

भारतीय की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतिया :–

(1) भारत ई–गवर्नेन्स, ई–मनी, ई–बैकिंग, ई–नाम, ई–कॉमर्श आदि के उपयोग को बढावा दे रहा है लेकिन सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत नहीं होने के कारण इसके क्रियान्वयन मे बाधा।

(2) राष्ट्रीय सुरक्षा व एकता अखण्डता को क्षति पँहुचायी है।

(3) साइबर आतंकवाद साम्प्रदायिकता, नक्सलवाद, जातिवाद, अलगाववाद, अतिवादी को प्रोत्साहित कर उन्हे वैश्वीकृत रूप दे रहा है जिससे देश की सुरक्षा, एकता, अविच्छिन्नता को आघात पहुचा है।

(4) साइबर सुरक्षा नीति, प्राधिकरण, IT act 2000, इस हेतु, कडे मानक तैयार करना, कडी सजा का प्रावधान, साथ ही रक्षा मंत्रालय, बैंक, सुरक्षा एजेंसियो के लिए उच्च तकनीक युक्त एंटी वायरस उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

19. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI ACT 2005) प्रमुख विशेषताऍ लिखिए एवं यह भी बताइये की इस अधिनियम के लागू होने के बाद पश्चात् प्रशासन में पारदर्शिता (TRANSPRANCY) एवं उत्तरदायित्व Accountability मे बढोतरी हुई हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005:–

GA CHAWALI ACADEMY

- किसी भी नागरिक को बहुत कम शुल्क पर वंछित सूचना प्राप्त करने में सहायक।
- वांछित सूचना उचित समयाबधि में नहीं मिलने पर अपील का प्रावधान
- इस हेतु केन्द्र में केन्द्रीय सूचना आयोग व राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन।
- राष्ट्र की सुरक्षा से जुडी हुई गोपनीय सूचनाएं मुहैया नहीं करवाई जाएगी।
- राज्य जिला, विभाग स्तर पर लोकसूचना अधिकारियों की नियुक्ति
- सूचना प्राप्त करने हेतु यदि आवेदन के साथ मात्र 10 रूपये शुल्क
- प्रशासन नागरिक अतः क्रिया में बढोतरी
- आसूचना एवं सुरक्षा संगठनों को छूट मानवधिकार व भ्रष्टाचार के मामलों में प्रकटन आवश्यक।

RTI के सकारात्मक प्रभाव :– <u>प्रशासन में पारदर्शिता में बढोतरी :–</u>

1. प्रशासन के सभी कार्यो की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होने लगी, जिससे व्याप्त् भ्रष्टाचार में कमी।
2. कई बडे घोटाले, स्कैम, भ्रष्टाचार, **RTI** की वजह से ही उजागर हुए है।
3. व्हीसल ब्लोअर्स सरंक्षण अधिनियम लाया गया।
4. विभिन्न घोटाले उजागर हुए जैसे 2जी स्पैक्ट्रम, कोयला आवटंन, आदर्श सोसायटी आदि।
5. प्रशासन को जनोन्मुख व निष्पक्ष बनाने मे मदद की है।

प्रशासन मे उत्तदायित्व में बढोतरी :–

1. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेहिता में वृद्वि होने के कारण उत्तरदायित्व मे बढोतरी
2. सरकारी योजनाओं को लाभ जनता के लक्षित समूह तक सुनिश्चित
3. सरकारी धन के अपव्यय मे कमी
4. नागरिक के प्रशासन व सरकार के प्रति विश्वास मे बढोतरी
5. लालफीताशाही जैसी बुराईयों पर इस अधिनियम की समयबद्वता के कारण अकुंश लग सका
6. लोकवित पर जनता का अधिकार सुनिश्चित हुआ है
7. सुशासन व लोककल्याणकारी राज्य के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक

नकारात्मक प्रभाव :–

1. सरकारी कार्मिको की ब्लैकमैलिंग
2. सूचना आयोग के पास मामलों की अधिकता
3. **RTI** कार्यकर्ताओं की हत्या
4. अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाना
5. जनसामान्य की समझ से परे
6. सुचनाए देने मे सरकारी धन का अपव्यय
7. लोक सेवको के कार्यभार मे वृदि
8. प्रशासनिक कार्यान्वयन व सहयोग मे अपेक्षित

GA
GEETANJALI ACADEMY